भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1218
दिनांक 11 फरवरी, 2025 / 22 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

वामपंथी उग्रवाद का उन्मूलन

1218. श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री दिलीप शइकीयाः
श्रीमती कमलेश जांगड़ेः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के लिए अपनाई गई नीति और अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान देश, विशेषकर छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की घटनाओं के आंकड़े क्या हैं;

(ग) प्रभावित जिलों में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा/घटनाओं की संख्या और प्रतिशत में कमी का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ से वामपंथी उग्रवाद को स्थायी रुप से समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): वामपंथी उग्रवाद (LWE) समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए, 2015 में "राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" को मंजूरी दी गई थी। एक बहु-आयामी कार्यनीति की परिकल्पना की गई है जिसमें सुरक्षा संबंधी उपायों, विकास हस्तक्षेपों, स्थानीय समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करना आदि शामिल है। सुरक्षा के क्षेत्र में, भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल प्रदान करके तथा राज्य पुलिस बलों के हथियारों और उपकरणों के आधुनिकीकरण व प्रशिक्षण, खुफिया जानकारी साझा करने हेतु एवं Fortified (फ़ोर्टीफ़ाइड) पुलिस स्टेशनों के निर्माण आदि के लिए धन प्रदान कर सहायता करती है। विकास के क्षेत्र में प्रमुख योजनाओं के अतिरिक्त, भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में

कई विशिष्ट पहलें की हैं, जिसमें सड़क नेटवर्क के विस्तार, दूरसंचार कनेक्टिविटी एवं कौशल और वित्तीय समावेशन में सुधार पर विशेष जोर दिया गया है।

(ख) और (ग): केंद्र और प्रभावित राज्यों के द्वारा वामपंथी उग्रवाद (LWE) से समग्र रूप से निपटने के लिए "राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना' के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप भौगोलिक प्रसार तथा हिंसा में लगातार गिरावट आई है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या में भी निरंतर कमी हुई है। इस सुधार की स्थिति को देखते हुए, पिछले छह वर्षों में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की तीन बार समीक्षा की गई है, जिसमें अप्रैल 2018 में 126 से 90 जिलों की कमी की गई, जो जुलाई 2021 में और कम होकर 70 और फिर अप्रैल 2024 में 38 जिले रह गए हैं। 2010 के उच्च स्तर की तुलना में 2024 में वामपंथी उग्रवादियों द्वारा की गई हिंसा में 81% की कमी आई है (2024: 374, 2010:1936)। इसी अवधि के दौरान परिणामी मौतों (नागरिक + सुरक्षा बल) में भी 85% की कमी आई है (2024: 150, 2010: 1005)।

छत्तीसगढ़ राज्य में, 2010 के उच्च स्तर की तुलना में 2024 में वामपंथी उग्रवादियों द्वारा की गई हिंसा में 47% की कमी आई है (2024: 267, 2010: 499)। इसी अवधि के दौरान परिणामी मौतों (नागरिक + सुरक्षा बल) में भी 64% की कमी आई है (2024: 122, 2010: 343)। पिछले पाँच वर्षों के दौरान वामपंथी हिंसा की घटनाओं का वार्षिक विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(घ): सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को वामपंथी उग्रवादियों द्वारा की गई हिंसा में मारे गए नागरिक/सुरक्षा बलों के परिवार को अनुग्रह राशि, सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण और ऑपरेशन संबंधी जरूरतों, आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों के पुनर्वास, सामुदायिक पुलिसिंग, वामपंथी उग्रवादियों द्वारा संपत्ति के नुकसान के लिए सुरक्षा बल कर्मियों/नागरिकों को मुआवजा आदि के प्रावधानों के जरिए क्षमता निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के तहत पिछले 5 वर्षों (2019-20 से अब तक) के दौरान सभी वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को 1925.83 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के लिए 829.80 करोड़ रुपये शामिल हैं।

विशेष अवसंरचना योजना (SIS) के जरिए विशेष बलों, विशेष खुफिया शाखाओं (SIBs) और जिला पुलिस को मजबूत किया जाता है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के लिए छत्तीसगढ़ के लिए 147 सहित 702 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन (FPSs) स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से छत्तीसगढ़ में 125 सहित 612 FPSs का निर्माण किया जा चुका है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1218, दिनांक 11.02.2025

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित अधिकांश जिलों में विकास को और गति देने के लिए, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सेवाओं में क्रिटिकल गैप्स को भरने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (SCA) योजना के तहत राज्यों को धन मुहैया कराया जाता है। इस योजना के तहत पिछले 5 वर्षों (2019-20 से अब तक) के दौरान सभी वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को 2384.17 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के लिए 773.62 करोड़ रुपये शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता (ACALWEM) योजना के तहत पिछले 05 वर्षों (2019-20 से अब तक) के दौरान हेलीकॉप्टरों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा शिविरों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को संबोधित करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को 654.84 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित विशिष्ट पहलें की गई हैं:

- वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में अब तक 4046 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है।
- दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार के लिए, 1333 टॉवर लगाए गए हैं।
- वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में स्थानीय आबादी के वित्तीय समावेशन के लिए, 1214 डाकघर खोले गए हैं। इसके अलावा, 297 बैंक शाखाएं और 268 ATM खोले गए हैं।
- राज्य में कौशल विकास के लिए, 09 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITIs) और 14 कौशल विकास केंद्रों (SDCs) को कार्यात्मक बनाया गया है।
- वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में आदिवासियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 45 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRSs) कार्यात्मक हैं।
- इसके अतिरिक्त, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CRPF, BSF, SSB और ITBP) स्थानीय लोगों के कल्याण और माओवादियों के प्रभाव से युवाओं को दूर रखने के लिए विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों (Civic Action Programme) का संचालन भी करते हैं।
- वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के जनजातीय युवाओं तक हमारी पहुंच बढ़ाने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS) के माध्यम से जनजातीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम (TYEPs) भी आयोजित किए जा रहे हैं।

*****

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1218 दिनांक 11.02.2025

अनुलग्नक

वामपंथी उग्रवाद हिंसा के पिछले पाँच वर्षों के आकड़ें

क्रम स.	वर्ष	सभी वामपंथी प्रभावित राज्यों में	छत्तीसगढ़
1	2020	470	241
2	2021	361	188
3	2022	413	246
4	2023	486	305
5	2024	374	267

******